



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1937 (श०)

(सं० पटना 684) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जून 2015

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

27 मई 2015

सं० प्र०-०१/आ०-(विविध)-०८/१५-१८०९/एम०—श्री हरिमोहन दास, तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति प्रभारी सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के बाबत अलग-अलग दो विभागीय कार्यवाहियाँ संचालित की गयीं। प्रथमतः श्री हरिमोहन दास, तत्कालीन प्रभारी सहायक खनन पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा के विरुद्ध नवादा एवं गया जिलों में पदस्थापन की अवधि में निम्नलिखित ग्यारह आरोपों के बाबत विभागीय अधिसूचना संख्या ज्ञापांक 238/एम० दिनांक 07.02.11 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया:

आरोप सं०-

1. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि में सर्वश्री विजय कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, अजय कुमार एवं नवीन सिंह को मौजा-पेस नवादा में उल्लिखित पट्टाधारियों को नियम की अवहेलना करते हुए खनन पट्टा स्वीकृत कराया गया जिसके फलस्वरूप फॉर्म डी चैप्टर-३ कंडिका-४ के प्रतिकूल कार्य करते सड़क से सटकर पचास मीटर की परिधि में उत्खनन कार्य किया गया है।

2. आपके द्वारा आवंटित लीज का लाभ उठाते हुए पट्टाधारियों द्वारा राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन का कार्य किया गया है जिसमें आपके द्वारा समुचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी जिससे अवैध खनन में सहयोग की संलिप्तता परिलक्षित होती है। आपका यह कृत अपने आप में दायित्वों एवं कर्तव्यों की प्रति लापरवाही का दूयोतक है।

3. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री बिन्देश्वरी पासवान एवं सुबोध कुमार को पेस नवादा में नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र में खनन कार्य हुआ नहीं पाया गया, लेकिन लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन हुआ जिसके नियंत्रण हेतु आपके द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखीय है कि लीज क्षेत्र में खनिज का निष्केप है ही नहीं।

4. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री अवधेश कुमार सिंह, फल्डू, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। साथ ही लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन कार्य सम्पन्न हुआ। इसके नियंत्रण हेतु आपके द्वारा नियमानुकूल अग्रेतर कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। ज्ञातव्य है कि लीज क्षेत्र में खनन का निष्केप नहीं है। लीज क्षेत्र में खनन कार्य तो नहीं हुआ जबकि मासिक विवरणी में एक खनन पट्टा से 24 हजार सी०एफ०टी० पत्थर और 50 हजार सी०एफ०टी० मोरम तथा दूसरे पट्टे से 27 हजार सी०एफ०टी० पत्थर और 41600 सी०एफ०टी० मोरम का प्रेषण प्रतिवेदित किया गया। इससे अवैध उत्खनन कार्य स्वयं सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा नियम के विरुद्ध जाकर वन सीमा से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी है।

5. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री राजेश्वर सिंह, फल्डू, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी साथ ही वन क्षेत्र में वन विभाग की स्वीकृति के बिना लीज स्वीकृत करायी गयी है जो नियम के विरुद्ध है। आपका यह कृत्य अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन कार्य सम्पन्न हुआ है जिसके नियंत्रण की दिशा में आपके द्वारा विधि सम्मत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं।

6. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री रंजीत सिंह, पचिया, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर एवं वन सीमा से सटकर लीज की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन हुआ है जिसके रोक-थाम की दिशा में पूरी उदासीनता बरतते हुए आपके नियंत्रण की दिशा में विधि सम्मत कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः इसके लिए आपक स्वयं जिम्मेवार एवं उत्तरदायी हैं।

7. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री कुलदीप यादव, पचिया, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन सम्पन्न हुआ है जिसपर नियंत्रण हेतु आपके विधि सम्मत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। आपका यह कृत्य अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति आपकी घोर उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। अतः इसके लिए आप उत्तरदायी हैं।

8. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री भूषण यादव, पचिया, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर एवं वन सीमा से सटकर नियम के विरुद्ध लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र में खनन कार्य किया हुआ तो नहीं पाया गया, लेकिन लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन कार्य हुआ जिसकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा कोई विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। अतः इसके लिए आप उत्तरदायी हैं।

9. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री नन्द कुमार, फल्डू, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन हुआ है जिसकी रोक-थाम की दिशा में आपके द्वारा कोई विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी। ज्ञातव्य है कि लीज के क्षेत्र में खनन निक्षेप नहीं है। लीज क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं हुआ है जबकि मासिक विवरणी में 38070 सी0एफ0टी0 पत्थर तथा 26765 सी0एफ0टी0 मोरम का प्रेषण प्रतिवेदित है। इसे अवैध खनन स्वतः प्रमाणित होता है।

10. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री रामाधार सिंह, हडिया, नवादा को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी के बगल में अवैध खनन हुआ है इसके रोक-थाम की दिशा में आपके द्वारा कोई विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। लीज क्षेत्र में खनन कार्य नहीं है एवं लीज क्षेत्र में खनन कार्य किया हुआ नहीं पाया गया।

11. आपके द्वारा नवादा जिला में पदस्थापन अवधि के दौरान सर्वश्री ललन कुमार एवं चन्द्र राजवंशी, सारसू, गया को नियम के विरुद्ध सड़क से सटकर लीज की स्वीकृति करायी गयी। लीज क्षेत्र में कोई खनन कार्य किया हुआ नहीं पाया गया लेकिन लीज क्षेत्र के बगल में राजगीर पहाड़ी में अवैध खनन कार्य सम्पन्न हुआ है। लीज क्षेत्र में मोरम एवं पत्थर के मात्र छोटे-छोटे टुकड़ों का निक्षेप है। अवैध खनन की रोक-थाम के लिए आपके द्वारा कोई भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके लिए आप उत्तरदायी हैं। ज्ञातव्य है कि लीज क्षेत्र में मोरम एवं पत्थर का छोटे-छोटे टुकड़ों का निक्षेप है।

जाँच प्राधिकार के द्वारा प्रस्तुत जाँच अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध निरूपित कुल 11 (ग्यारह) आरोपों में से आरोप सं0 02,03,04,06,07,08,09,10 एवं 11 को पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप सं0 01 एवं 05 को आशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। पत्रांक 1747 दिनांक 24.04.14 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा मांगी गयी। आरोपित पदाधिकारी श्री दास ने अपने जवाब में लगाये गये आरोपों को अमान्य किया, परन्तु अपने जवाब की पुष्टि में अलग से कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया है, बल्कि पूर्व के स्पष्टीकरण में वर्णित बिन्दुओं को ही दोहराया है। सम्यक् समीक्षोपरांत द्वितीय कारण पृच्छा पर उनके जवाब को सही नहीं पाने के कारण अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित गंभीर आरोपों के दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (XI) के अन्तर्गत “सेवा से बर्खास्तगी” का वृहद् शास्ति अधिरोपण का अंतरिम निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त वृहद् शास्ति अधिरोपण के प्रस्ताव पर पत्रांक 2922/एम0, दिनांक 23.07.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श मांगा गया। आयोग ने अपने पत्रांक 2641 दिनांक 09.02.15 द्वारा प्रस्तावित दण्ड से असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दण्ड को आनुपातिक नहीं होने का परामर्श अंकित किया है। किन्तु आयोग ने उक्त वृहद् दण्ड को समानुपातिक नहीं मानने का कोई आधार / कारण नहीं दिया है, यद्यपि आरोपित के विरुद्ध अवैध खनन जैसे 11 (ग्यारह) आरोपों में 9 पूर्णतः तथा दो आशिक रूप से प्रमाणित पाये गये हैं जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई तथा वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। ये सारे आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं अतः उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय समानुपातिक पाया गया है। श्री दास का आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है तथा उपरोक्त कृत्यों के आलोक में वह बिहार सरकार की सेवा में रहने के योग्य नहीं हैं।

अतः सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार (सरकार) द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत प्रस्तावित दण्ड को समानुपातिक पाते हुए इन प्रमाणित गंभीर आरोपों में श्री हरिमोहन दास, तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी, नवादा को पूर्णरूपेण दोषी पाते हुए राज्यहित एवं प्रशासनिक हित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (XI) के तहत “सेवा से बर्खास्तगी” जो समान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्वहता होगी” शास्ति अधिरोपण का अंतिम निर्णय लिया गया है।

2. इसके अलावा बन्दोबस्ती वर्ष 2004 एवं 2005 में नवादा जिले में बालूधाटों की बन्दोबस्ती में काफी बड़ी वित्तीय क्षति (‘175.00 लाख) के बाबत श्री दास के विरुद्ध तीन आरोप (प्रपत्र ‘क’) गठित कर ज्ञाप सं0 159/एम0 दिनांक

16.01.07 द्वारा आरोप-पत्र निर्गत कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय विभागीय ज्ञापांक 588/एम0 दिनांक 22.03.07, 2124/एम0 दिनांक 17.11.08 एवं ज्ञापांक 1458/एम0 दिनांक 12.08.09 द्वारा लिया गया।

आरोप संख्या-1

- I. वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रभारी सहायक खनन् पदाधिकारी, नवादा द्वारा खनिजों से कुल 424.80 लाख रूपये की राजस्व वसूली का प्रतिवेदन दिया गया था। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति वित्तीय वर्ष 2005-06 में खनिजों से प्राप्त राजस्व का चालानवार सत्यापन कोषागार से कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- II. विभाग को माह सितम्बर, 06 तक नवादा जिले का वित्तीय वर्ष 2005-06 के राजस्व समाहरण का कोषागार से चालानवार सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 14.08.06 के मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिवेदन की जानकारी मांगी गयी तो प्रभारी सहायक खनन् पदाधिकारी, श्री श्याम नारायण सिंह द्वारा अनौपचारिक रूप से सूचना दी गयी कि वर्ष 2005 में बालूधाटों की बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति ने कार्यालय में 68 लाख रूपये जमा करने के प्रमाण के रूप में चालान की जो प्रति जमा की, उसे बैंक / कोषागार से सत्यापन के बाद जाली पाया गया है।
- III. वर्ष 2005 के लिए बालूधाटों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई दिसम्बर, 04 में समाहरणालय में हुई थी एवं श्री अरूण यादव ने कुल 22400500/- रूपये पर बन्दोबस्ती लिया था। बन्दोबस्ती की राशि के विरुद्ध जमा किये गये 68 लाख रूपये के चालान की प्रति जिसे कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, उसे कोषागार से सत्यापन में जाली पाया गया। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-
 1. 2000000/- (बीस लाख) रूपये दिनांक 31 जुलाई 2005 चालान सं-19
 2. 2000000/- (बीस लाख) रूपये दिनांक 1 अगस्त 2005 चालान सं-41
 3. 2800000/- (अटाईस लाख) रूपये दिनांक 29 अक्टूबर 2005 चालान सं-27
- IV. विभाग को अनौपचारिक रूप से इसकी सूचना प्राप्त होने पर सरकार के निर्णयोंपरांत मामले के अनुसंधान के लिये आरक्षी अधीक्षक, नवादा को पत्रांक 51/एम0सी0 दि0 18.08.06 से सूचना दी गयी। कालान्तर में जांचोपरांत यह पाया गया कि पंचांग वर्ष 2005 के लिए दी गयी बन्दोबस्ती में बन्दोबस्तधारी द्वारा कुल नीलामी राशि 224.00 लाख रूपये के विरुद्ध मात्र 110.61 लाख रूपये ही जमा किये गये। शेष राशि 113.39 लाख रूपये जमा नहीं किये गये एवं इसमें से 68 लाख रूपये के लिए जाली चालान कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। बन्दोबस्तधारी श्री अरूण यादव को जब उनके द्वारा दिये गये पते पर खोज की गयी तो यह पता चला कि अरूण यादव नाम का कोई व्यक्ति उस पता पर नहीं रहता है जो कार्यालय अभिलेखों में अंकित है।
- V. जाँच में यह पाया गया कि पंचांग वर्ष 2004 के लिए बालूधाटों की बन्दोबस्ती श्री कारू यादव को 203.55 लाख रूपये में दी गयी थी। बन्दोबस्ती की कुल राशि में से मात्र 96.50 लाख रूपये ही बन्दोबस्तधारी द्वारा जमा किया गया, शेष 107.05 लाख रूपया उनके उपर बकाया था परन्तु कार्यालय द्वारा मात्र 26 लाख रूपये ही संचिका में बकाया दिखाया गया था। इस प्रकार विगत दो वर्षों में नवादा में बालूधाटों के बन्दोबस्ती के विरुद्ध सरकार को 220.44 लाख रूपये की क्षति हुई।

आरोप संख्या-2-

विभागीय अभिलेखों के अनुसार बालूधाटों के बन्दोबस्ती से हुई क्षति की अवधि में आप प्रभारी सहायक खनन् पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित थे। मामले की समीक्षोपरांत निर्मांकित आरोप आपके विरुद्ध निर्धारित किया जाता है:-

बालूधाट की बन्दोबस्ती हेतु निर्गत दिशा निर्देश संख्या 2442/एम0 दिनांक 24.10.2003 तथा पत्रांक 2292/एम0, दिनांक 05.11.04 में निहित निर्देश के अनुसार आपका दायित्व था कि बन्दोबस्तधारी से निर्मांकित कागजात एवं राशि प्राप्त करते:-

- I. स्थायी पता प्रमाण पत्र / चरित्र प्रमाण-पत्र।
- II. सुरक्षित जमा राशि की आधी राशि / कारोबार संबंधी बैंक सोलेभेन्सी।
- III. बन्दोबस्ती के लिए विहित प्रपत्र 'ओ' में एकरानामा किया जाना।
- IV. नीलामी के अगले कार्य दिवस को उच्चतम डाकवक्ता से आधी राशि जमा करना।
- V. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / समिति से वाणिज्यकर / आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।

इसके अतिरिक्त नीलामी की आम सूचना के निर्मांकित शर्तों का अनुपालन कराते :-

- i. उच्चतम डाकवक्ता से नीलामी की 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूत राशि में जमा करना।
- ii. बन्दोबस्ती के उपरांत 15 अप्रैल 04 एवं 15 जुलाई 04 को दो बराबर किस्तों में बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि प्राप्त किया जाना।
- iii. उच्चतम डाकवक्ता के प्रथम किस्त के भुगतान के बाद शेष राशि के भुगतान के लिए बैंक गारंटी लिया जाना।
- iv. बन्दोबस्तीधारी को जिला खनन कार्यालय से सत्यापित एवं मोहरित फार्म 'एफ' में परिवहन के लिए सुनिश्चित किया जाना।
- v. प्रत्येक माह के अनुवर्ती माह की पन्द्रह तारीख तक जिला खनन कार्यालय में उत्पादन, प्रेषण का रिटर्न बन्दोबस्तधारी से प्राप्त किया जाना।
- vi. बन्दोबस्तधारी द्वारा किसी भी शर्त एवं बंधेज का उल्लंघन करने पर शेष अवधि के लिए बन्दोबस्ती रद्द कर प्रतिभूत राशि जब्त किया जाना।

उपर्युक्त उल्लेखित दायित्वों का निर्वाह नहीं करने के कारण वर्ष 2004 में बन्दोबस्ती की संचिका में आधी राशि 101.77 लाख रूपये जमा किये जाने की विस्तृत विवरणी नहीं रहने पर भी आपके द्वारा उसकी जाँच नहीं की गयी एवं उसे

अनुमोदित किया गया। सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि सरकारी कोष में वास्तव में आधी राशि से 61.50 लाख रूपये कम जमा था।

इसी प्रकार वर्ष 2005 में भी बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती की आधी राशि 113.39 लाख रूपया जमा किया गया अथवा नहीं, इसकी जाँच कराये बिना क्षेत्राधिकार दे दिया गया। क्षेत्राधिकार दिये जाने संबंधी टिप्पणी सचिका में अंकित नहीं की गयी। कोषागार से जाँच कराने पर यह पाया गया कि बन्दोबस्तधारी द्वारा नियमानुसार आधी राशि 113.39 लाख रूपया में से 45.39 लाख रूपया कम जमा किया गया था।

आरोप संख्या-3-

उपरोक्त कोडिका-1 में वर्णित घटनाक्रम एवं कोडिका-2 के आरोप से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आपके द्वारा नवादा जिला के बालूघाटों की बन्दोबस्ती में नियमों तथा विभागीय मार्गदर्शन एवं दिशा निदेश का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार आपने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप सरकार को 106.89 लाख रूपये की क्षति हुई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अधिगम में उक्त तीन आरोपों को आंशिक रूप से जाँच प्रमाणित पाया गया। बड़े पैमाने पर राजस्व क्षति होने, समाहर्ता को वस्तुस्थिति अवगत नहीं कराने, तथा कार्यालय प्रधान होने के नाते सत्यापन आदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण जाँच प्राधिकार के अभिमत से असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार ने पत्रांक 1753 दिनांक 24.04.14 द्वारा आरेपित पदाधिकारी श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की। श्री दास ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में स्वीकार किया है कि उपरोक्त राजस्व की हानि सरकार को हुई है, किन्तु इसके लिए उहोंने बहाना बनाकर दूसरे पदाधिकारियों / कर्मचारियों यथा श्री श्याम नारायण सिंह, खान निरीक्षक तथा श्री मुनेश्वर राम, लिपिक, श्री नारायण राम, तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी एवं श्री बोध नारायण जी विमल, खान निरीक्षक पर दोष डालें। ज्ञातव्य है कि उक्त समय नवादा जिला खनन कार्यालय के प्रधान श्री दास ही थे, इसलिए सरकार को राजस्व की क्षति न हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए श्री दास मुख्यतः दोषी हैं। श्री दास ने समाहर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया तथा बन्दोबस्तधारी का सत्यापन नहीं किया था। जहाँ तक अन्य पदाधिकारी / कर्मचारी का प्रश्न है, श्री श्याम नारायण सिंह अन्य मामले में बर्खास्त हैं एवं इस मामले में भी दण्डित किये गये हैं। श्री बोध नारायण जी विमल, खान निरीक्षक के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही चल रही है। श्री मुनेश्वर राम का स्थानान्तरण झारखण्ड (राँची) हो गया है। अतः झारखण्ड सरकार / निदेशालय उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम है। इसी मामले में श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन आशुटंकक को भी दण्डित किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि इस मामले में श्री दास सहित कई व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी। सम्यक् समीक्षोपरांत श्री दास की कर्तव्यहीनता, मिलीभगत, बद्नीयती आदि के कारण सरकार को ₹ 1.75 करोड़ की क्षति हुई है। ये आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं और इससे यह सिद्ध होता है कि श्री दास का आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है तथा प्रशासनिक अक्षमता के कारण सरकारी सेवा में रहने योग्य नहीं है।

3. अतः उपर्युक्त दोनों मामले को एक साथ सम्बद्ध करते हुए श्री हरिमोहन दास, तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा सम्प्रति प्रभारी सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर को राज्यहित एवं प्रशासनिक हित में तात्कालिक प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (XI) के तहत “सेवा से बर्खास्तगी जो समान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहता होगी” शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

बर्खास्त पदाधिकारी का व्यक्तिगत विवरण:-

नाम- श्री हरिमोहन दास,

पिता का नाम- श्री समचरित्र दास

पता- सूर्या बिहार कॉलोनी, फेज-2, आशियाना नगर, पटना

जन्म तिथि - 07.01.1958

खान निरीक्षक पद का पदभार ग्रहण-04.05.1982

सेवा सम्पुष्टि की तिथि- 05.01.1990

प्रोन्ति का पद (वर्तमानधारित)-खनिज विकास पदाधिकारी, प्रभारी सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, भागलपुर।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मा० हसनैन खाँ,

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 684-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>